

हो गये सैनिकों के आश्रितों के पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार युद्धभूमि में मारे गये अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो गये भारतीय शांति सेना के जवानों के आश्रितों के लिये सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ पद आरक्षित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता-मणि पाणिग्रही) : (क) जिन जवानों की युद्ध में मृत्यु हो जाती है या जो गम्भीर रूप से निशक्त हो जाते हैं (निशक्तता 50% से अधिक हो जाती है या रोजगार के लायक नहीं रह जाते हैं), उन पर आश्रित दो व्यक्तियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से केन्द्र सरकार के अधीन भरे जाने वाले समूह "ग" और "घ" पदों पर नियुक्ति करने के लिये "11-क" प्राथमिकता दी जाती है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/आश्रित अपना रोजगार स्थापित करने के लिये भी कुछ रियायतें पाने के पात्र हैं। सुरक्षा कार्मिकों के लिये आरक्षित कोटे में से वे तेल उत्पादों की कुछ एजेंसियाँ आवंटित बिम्बे जाने के भी पात्र हैं।

(ख) और (ग) रक्षा सेवाओं के जिन कार्मिकों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों अर्थात् उनका पुत्र/पुत्री, नजदीकी रिश्तेदार रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराये बिना रिकार्ड कार्यालय/रेजीमेंटल केन्द्र। मृतक की अपनी मूल कोशों या यूनिटों। सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों तथा अन्य रक्षा स्थापनाओं में उपलब्ध समूह "ग" अथवा समूह "घ" के उपयुक्त सिविल पदों पर नियुक्ति के पात्र होते हैं, बशर्ते वे इन पदों पर नियुक्ति के लिये निश्चित आयु तथा शैक्षिक अर्हतायें

पूरी करते हों। युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करने वाले भारतीय शांति सेना के जवानों के आश्रित भी उपयुक्त रियायतें प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त वीरगति प्राप्त भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर भारत सरकार में नौकरियाँ देने का भी प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार के अधीन उनके पुनर्नियोजन के अतिरिक्त रक्षा मंत्री ने विभिन्न राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को भी लिखा है और जहाँ आवश्यक हो, नियमों में छूट देकर अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिये उनका सहयोग माँगा है। राज्यों। संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से यह अनुरोध जारी करने के लिये भी अनुरोध किया गया है कि जब कभी भी वीरगति को प्राप्त भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के आश्रित रोजगार कार्यालय के माध्यम से, जहाँ कि उनके नाम उच्च प्राथमिकता के आधार पर भेजे जाते हैं, रोजगार प्राप्त करने हेतु अनुरोध करें, उन्हें तत्काल समुचित रोजगार देने के लिए विशेष प्रयास किये जायें।

Production Of Indigenous Submarine

1113. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether indigenous as well as Soviet alternatives to the West German submarine are being explored following the decision to terminate the HDW programme and not to place the order with the HDW shipyard for the fifth and sixth submarines; if so, the details thereof;

(b) whether the delay in finalising the deal will greatly affect India's defence preparedness in regard to naval forces; and

(c) if so, by when the final decision in this regard is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) to (c) A proposal for the acquisition of additional submarines is under consideration of the Government. Further details cannot be disclosed in the interest of national security. The Government always take adequate measures to ensure full defence preparedness at all times.

Concentration of Pakistani Forces on Siachen

1114. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistani forces have been heavily concentrating on Siachen for the last three or four months;

(b) whether the latest weapons and aircraft acquired by Pakistan have been deployed there;

(t) whether this has caused great imbalance [in the defence needs of India;

(d) if so, in view of the heavy concentration of Pak Forces in this area, what steps Government propose to take to meet the situation; and

(e) what is the total number of occasions on which Pakistani attack was repulsed upto June, 1988?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) and (b) Pakistan has inducted additional troops in the Siachen Glacier area during the last few months. The latest equipment received by Pakistan is being gradually absorbed by her troops including those deployed in the Siachen area.

(c) and (d) Our troops in the Siachen area are adequately prepared

and suitably deployed to meet any contingencies.

(e) During the period from 1984 till June 1988, Pakistani troops had unsuccessfully attacked Indian positions in the area on five occasions.

Agreement between LTTE and Indian Government

1115. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement was worked out between LTTE representative Krishna Kumar alias 'Kittu' and the Indian Government in Madras recently; and

(b) if so, what are the details of the points that have been worked out in the said agreement and the points still unresolved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH I: (a) No, Sir.

(b) Does not arise. .

Safety of Nuclear Power Plants

1116. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Emergency Response Committee under the Atomic Energy Commission has prepared plans to ensure safety of nuclear power plants; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) and (b) A National